



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1464]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936

No. 1464]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

का.आ. 1821(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 753(अ), तारीख 11 मार्च, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 13 मार्च, 2014 में प्रकाशित की गई थी, के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) और उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिला सम्बलपुर, ओडिशा (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि में और उस पर के अधिकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, तारीख 13 मार्च, 2014 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :—

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;
- (2) अधिकरण का गठन शर्त (1) के अधीन, सरकारी कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन किया जाएगा तथा ऐसे अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार, उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;

- (4) सरकारी कंपनी के पास केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमियों और अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/28/2010—पीआरआईडब्ल्यू—I]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2014

S. O. 1821(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 753(E), dated the 11th March, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 13th March, 2014, issued under Sub-section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all the rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of Section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Mahanadi Coalfields Limited, District Sambalpur, Odisha (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby directs, that the said lands and rights in or over the said lands so vested shall, with effect from the 13th March, 2014, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (1) The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;
- (2) A Tribunal shall be constituted under Section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vesting, shall also be borne by the Government Company;
- (3) The Government Company shall indemnify the Central Government or its officers against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officers, regarding the rights in or over the said lands so vested;
- (4) The Government Company shall have no power to transfer the said lands and the rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
- (5) The Government Company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/28/2010-PRIW-I]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.